

काफी कम्पलीकेटेड हो जाता है। क्या मंत्री महोदय, इस प्रक्रिया को इतना सीधा और सरल बनाएंगे जिससे उनको पेंशन पाने में सुविधा हो ?

श्री चरण सिंह : माननीय मित्र ने जो कहा है, वह बहुत ठीक है। मैं उससे सहमत हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास यह आदेश भेज रहे हैं कि वह अपनी ओर से तहकीकात करें न कि इस बात पर निर्भर करें कि आश्रितों के यहां से दरखास्त आये।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि जो ग्रैंडर ट्रायल थे, जिनकी टाचंस की वजह से मृत्यु हो गई, क्या उनको भी पेंशन दी जाएगी ?

श्री चरण सिंह : टाचंस की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई, और वह ग्रन्डर थे, वह तो इसमें आ गए।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : वह ग्रैंडर ट्रायल थे, मीमा में डिटेनम नहीं थे।

श्री चरण सिंह : उन केमेज पर विचार किया जाएगा।

SHRI SAMAR GUHA: Sir, I want to know from the hon'ble Minister whether it is a fact that on the basis of a circular issued by the Home Minister during the last regime many teachers in schools, colleges and universities were deprived of their salaries? This circular was sent to all the State Chief Secretaries. It was said in that circular that those teachers who are in detention under MISA should not be given full salary. They should be paid salary only for the period of leave. I would like to know whether that circular will be withdrawn so that the concerned authorities may be able to pay the outstanding salaries to the affected teachers?

SHRI CHARAN SINGH: Sir, this supplementary does not arise out of the present question. I want a separate notice for it.

SHRI PURNA SINHA: May I know from the hon'ble Minister what steps will be taken in the cases of those who suffered incurable diseases during detention resulting into eventual death after three months?

SHRI CHARAN SINGH: Sir, I have not understood the question but those cases where death has occurred will be covered and given pension.

Memoranda Against Chief Minister/ Ex-Chief Ministers etc.

*352. SHRI KANWAR LAL GUPTA. Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether Government have received memoranda against some Chief Ministers, Ministers, ex-Chief Ministers and ex-Ministers of the States in the last two years;

(b) if so, the names of persons against whom the memoranda have been received and the contents of the memoranda; and

(c) what action has been taken over these memoranda by the Government; and whether Government propose to refer these memoranda to CBI for investigation?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS: (SHRI CHARAN SINGH): (a):

Yes, Sir.

(b) It will not be appropriate to disclose the nature of the allegations contained in the said memoranda received during the years 1975 and 1976 or the names of the persons against whom allegations were made.

(c) According to the available information the said memoranda were processed in accordance with the usual procedure having regard to the provisions of the Code of Conduct for

Ministers and the merits and the circumstances of each case. There is no proposal to refer them for investigation to the C.B.I.

श्री कबंर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आप ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि कर्नाटक, आराम और दूसरे प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के खिलाफ मेमोरेण्डम सरकार के पास आए हैं और सरकार ने उन्हें उन के कमेंट्स के लिए भेजा है, और यह भी कि डम बारे में क्या कार्यवाही हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जब से वह होम मिनिस्टर बने हैं, तब से—इन तीन महानों में—उनके पाम बिजने मेमोरेण्डम आए हैं, और उन में मोटे तौर पर—वह इंटिन्ज न दें—क्या—क्या एली-गेशन्ज है। मंत्री महोदय ने यूज्युअल प्रोसीजर की बात कही है।

I would like to know what the usual procedure is and what the provisions of the Code of Conduct are to which he has referred in his reply.

श्री चरण सिंह : मूल सवाल तो पिछले दो साल के बारे में था। माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा है कि जब से गवर्नमेंट आई है, तब से कितने मेमोरेण्डम आए हैं। मैंने उन्हें गिना नहीं है। लेकिन वह एक दर्जन के लगभग होंगे। उन के खिलाफ शिकायत तो वही हैं, जो आम तौर पर राजनीतिज्ञों के खिलाफ होती हैं—अपनी पावर का दुरुपयोग करने की। उन सब को मुनाना मुझे इसमें गुरेज नहीं हैं, और न ही मैं कोई बात छिपाना चाहता हूँ—मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। उन से टिप्पणियां मांगी गईं, और अगर उन्हें असंतोषजनक पाया, तो उनके खिलाफ कमीशन आफ एनक्वायरी नियुक्त कर दिए गए।

श्री कबंर लाल गुप्त : मंत्री महोदय, ने कहा है कि टिप्पणियां मांगने के बाद जहां मुनासिब समझा गया, वहां कमीशन आफ एनक्वायरी नियुक्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जिन के खिलाफ कमीशन आफ एनक्वायरी नियुक्त किए गए हैं यह मान लिया गया है कि उनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस है। तो मंत्री महोदय कम से कम उन के नाम तो बता दे—वह नहीं बताना चाहते तो वह यह बताए कि लोकपाल और नोकायुक्त के सम्बन्ध में बिल सरकार कब पेश करेगी। अब केन्द्र में, और बहूत से राज्यों में भी, जनत पार्टी की सरकार है। क्या सरकार ने मंत्रियों के लिए कोई आचार संहिता बनाई है, जिससे उन के खिलाफ भी इस प्रकार के करप्शन के चाजिज आए ? क्या डम बारे में कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री चरण सिंह : जहां तक लोकपाल विधेयक का प्रश्न है, उस पर गृह मंत्रालय में विचार हो रहा है और करीब करीब वह तैयार हो चुका है। लोकपाल की परिधि में इस गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, प्रदेशों के मंत्रि-मंडलों के मुख्य मंत्री भी इस की परिधि में हैं—सिर्फ उन के अपने दुराचरण के लिए नहीं, बल्कि अगर वे दूसरे मिनिस्टर्स के कदाचार, और करप्शन की अभियानत, एवेटमेंटर करें, तो उस के लिए भी। अगर आप इजाजत दे, तो सब माननीय सदस्य भी उसकी परिधि में आने वाले हैं—सिर्फ यह नहीं कि उन्होंने मौजूदा पार्लियामेंट की अवधि में कोई गलती की हो। बल्कि अगर पिछले पांच साल में उन्होंने कोई गलती की हो, जब कि वे मिनिस्टर या मेम्बर रहे हों तब भी वे उस की परिधि में आने वाले हैं। वह विधेयक कब तक

स्टचूट बुक पर रखा जा सकेगा । यह लोक सभा और राज्य सभा के ऊपर होगा । मैं समझता हूँ कि इस जुलाई के अन्त तक हम उस को इन्ट्रोड्यूस कर देंगे ।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: Sir, I am very happy that the hon. Minister did not mention the names in his reply. I would like to know from the hon. Minister whether he has adopted such procedure with regard to the memoranda received by him from our Janata friends against all the Chief Ministers. I know that the contents of a memorandum were published in news papers and broadcast by All-India Radio prominently in English bulletins. Is it the procedure? You said that there is Code of Conduct with regard to the Ministers. I know that in a particular case—I have strongly protested—even before the Home Minister received the memorandum, it was broadcast by the All-India Radio and published in the newspapers. I would like to know how it happened.

SHRI CHARAN SINGH: Sir, the hon. Member is right to a certain extent. It was in only one of the cases that that mistake was committed. I am sorry for it. But in no other case it was committed.

SHRI CHARAN NARZARY: I would like to know whether it is a fact that the Central Government received charge-sheets against the Chief Minister of Assam and his company. If so, what are the charges made therein and whether any demand has been made in the charge-sheets.

MR. SPEAKER: I wonder if you have information about Chief Minister of each State in the country.

SHRI CHARAN SINGH: It is correct that a memorandum against the Chief Minister of Assam—perhaps it is Assam that the hon. Member was referring to—has recently been received.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It contains 75 allegations.

SHRI CHARAN SINGH: I do not know the number.

SHRI SHEO NARAIN: Will the hon. Minister give us the substance of the memorandum?

MR. SPEAKER: That will be placed on the table of the House.

श्री चरण सिंह : उनमें एक बड़ा आरोप यह है कि नवम्बर 1976 में गौहाटी में जो कांग्रेस का इजलाहा हुआ था उसमें स्टेट फंड्स का बहुत दुरुपयोग हुआ और बहुत सी शिकायतें हैं ।

SHRI SONU SINGH PATIL: Will the hon. Minister circulate for the information of the House the broad features of the Code of Conduct for the Ministers as well as the Member of Parliament?

SHRI CHARAN SINGH: There was a Code of Conduct arrived at—perhaps, during Pandit Jawaharlal Nehru's time in 1964—I have myself not read it. But I have no objection to sending a copy to the hon. Member.

श्री हुकूम चन्द कच्छबाब : जैसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जंत्रों शिकायतें उनके पास आई हैं क्या इन शिकायतों में ऐसे लोगों की शिकायतें भी हैं जो कांग्रेसी सरकार में मंत्री थे । क्या उनके खिलाफ भी आरोप लगे हुए हैं और अब वे जनता पार्टी में आने का प्रयास कर रहे हैं या बहुत से आ भी गए हैं ? क्या उनके खिलाफ भी आप जांच करवाएंगें ? दूसरे, यह कि आपकी जांच कब तक पूरी हो जाएगी और कब तक उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह तो सभी लोग इसमें आएंगे । जनता पार्टी में पहले थे या नहीं, बाद में आए

या नहीं आए सभी उस के अंदर आते हैं। चाहे वे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे इधर के बैठने वाले हों, लोकपाल ऐक्ट की परिधि के अंदर सभी लोग आ जाएंगे।

SHRI SOMANATH CHATTERJEE: May I know from the hon. Minister whether, in the context of the last Assembly elections and the new Governments that have come in different States, he will consult the new State Governments and the Chief Ministers before taking any decision in respect of these memoranda which have been submitted?

SHRI CHARAN SINGH: I think the question is whether the present Chief Ministers will be consulted. Yes, they will be consulted and where the investigations are not complete—they are not complete in almost all the cases—they will be sent to the concerned Chief Minister and it will be for him to make enquiries.

SHRI K. LAKKAPPA: Mr. Speaker. I welcome the statement made by the Prime Minister recently that corruption in public life will be dealt with by appointing Lok Pals and other measures. I do not want to drag anybody's name. There are certain serious charges levelled against the ex-Chief Ministers of Karnataka and in order to escape certain charges made against them, they have already joined the Janata Party. May I know whether the serious charges levelled against those persons also will be dealt with on the same footing and on the same principles you have stated now?

SHRI CHARAN SINGH: A commission has already been appointed by the Karnataka Government to look into the charges against those ministers who held office previously. The Government cannot appoint a second commission to go into them.

SHRI K. LAKKAPPA: Serious charges have been made against two ex-Chief Ministers of Karnataka. An

enquiry commission has been appointed by the State Government. But they have joined the Janata Party and therefore, there is a doubt that they may go scot-free.

SHRI VAYALAR RAVI: The minister said, he is not in a position to appoint a second commission because the State Government has already appointed a commission to look into the charges against two-ex-Chief Ministers and the present Chief Minister. Apart from that, you have appointed another commission to look into the charges against the present Chief Minister. How do you reconcile the two?

MR. SPEAKER: The question is very clear, whether the ex-Chief Ministers also will be covered by this enquiry. Let him answer yes or no.

SHRI CHARAN SINGH: The Chief Minister of Karnataka has appointed a commission ...

SHRI VAYALAR RAVI: For himself?

SHRI CHARAN SINGH: For himself only those cases which do not pertain to corruption, only irregularities. It is the Central Government's Commission which will look into the charges of corruption against him and his colleagues. The commission which he has appointed against himself does not contain charges of corruption. (*Interruptions*).

SHRI K. LAKKAPPA: He must give correct information.

MR. SPEAKER: He has not finished his reply. When you say correct information, you do not mean to say that you must get information which is satisfactory to you. He has to give whatever information he thinks is correct. It may not be to your liking, but that is a different matter. You must take whatever information he gives and probe into it further later on.

SHRI CHARAN SINGH: As you have pointed out, I have not yet finished my reply. The gentleman stood up and shouted. Hard words break no bones. Let me finish my reply. There are other allegations about which no names have been mentioned. They may refer to the previous Chief Ministers or not. Those allegations are also being looked into by the commission appointed by the Chief Minister.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन के मंत्रालय की ओर से क्या सावधानी बरती जाती है जिसे यह मालूम हो कि कमीशनों की नियुक्ति मनमाने ढंग से न की जाए ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सावधानी का प्रश्न नहीं है। 1952 के कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अधीन स्टेट गवर्नमेंट को कमीशन नियुक्त करने का अधिकार है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी है। लेकिन किन्हीं मामलों में जब एक कमीशन नियुक्त हो जाए चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा हो या प्रदेशीय सरकार द्वारा हो तो उन्हीं मामलों की जांच करने के लिए कोई दूसरी सरकार कमीशन नियुक्त नहीं कर सकती है।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: My question is: Was any precaution taken by the Ministry of Home Affairs to convince everybody that the appointment of these Commissions is not done on an arbitrary basis?

SHRI CHARAN SINGH: The Government of India has no powers to prevent Chief Ministers of the State Governments from appointing Commissions.

श्री भानूकुमार शरत्री : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री

भी इस भ्रष्टाचार के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने एक प्रेस वक्तव्य में यह कहा था कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल मुख्वाड़िया के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके बारे में जांच कमीशन शीघ्र नियुक्त करने वाले हैं। क्या वह कमीशन आप शीघ्र ही नियुक्त करने वाले हैं ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पब्लिक मीटिंग में जब मुझमें पूछा गया था कि क्या आप सादही माना काण्ड के बारे में कोई जांच करेंगे तो मैंने कहा था कि की जायगी। इसी पृष्ठभूमि में मैंने यह कहा था। लेकिन बाद में मुझको मालूम हुआ कि सादही माना काण्ड की पहली इन्क्वायरी हो चुकी है और उसमें श्री मोहन लाल मुख्वाड़िया को दोषी नहीं पाया गया। कुछ और शिकायतें ध्यान में आई हैं और जहाँ तक मुझे पता है उनको हमने स्टेट गवर्नमेंट के पाम इन्क्वायरी के लिए भेज दिया है।

SHRI L. K. DOLEY: So far as the question of allegation against the Assam Chief Minister is concerned, the Home Minister refers to the last AICC Session held at Gauhati. Well, it was a session jointly hosted by the eight border States of North-eastern region like Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura etc. At a time when there was no Janata Party of today to assume importance of national character, it was the boundan duty of the Congress at that time to promote emotional sense of unity and integration in those border States which are politically so seismic. I do not know about the exact financial implication involved in it. But in the context of the magnitude of such a big conglomeration of people in a small city like Gauhati was it

not necessary for the Assam Government to make adequate preparations for accommodating those people in order to avoid anomalies and other disorderliness at that time?

SHRI CHARAN SINGH: Sir, this is the plea taken up by the Chief Minister of Assam to which the hon. Member is referring. Now it is for the Commission of Enquiry which is actually appointed to look into this to decide whether the State of Assam was entitled to spend crores and crores of their money on this.

MR. SPEAKER: Question Hour is over now.

RE: SHORT NOTICE QUESTIONS

SHRI K. LAKKAPPA: I have a submission. Yesterday there was a point of order. There is no point of order now on this issue. I will draw your kind attention to rule 54(2) of the Rules of Procedure, viz.

(2) If the Minister concerned agrees to reply, such question shall be answered on a day to be indicated by him....

I will make a humble request. The Prime Minister is also present here. All the Short Notice Questions comprising all the reasons and details of public importance involved, were submitted from the Congress side; but not even one question has been admitted in this session. The Minister has admitted this. I would like to know whether this government is run only for their own private purposes.

MR. SPEAKER: Mr. Lakkappa, you have brought it to their notice. Please sit down. The Prime Minister and other Ministers have also been hearing. But for all practical purposes, Mr. Jyotirmoy Bosu is not in the Janata party. I am sure he will not accept it, even if you permit.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Order now, Mr. Lakkappa, you have brought it to notice in a dignified way. Let them answer.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I make no difference between Members of the Opposition and Members on this side, in the matter of Short Notice Questions, or of any other questions. I would like to see as many Short Notice Questions as are possible to be replied to. Only in regard to those which have no particular importance immediately, we say 'No'. Otherwise, we want to reply to all Short Notice Questions; and we don't want to evade them. I think my colleagues will also follow the same policy. But I hope you will also follow the same policy.

MR. SPEAKER: Now Short Notice Question No. 12. Mr. Jyotirmoy Bosu.

SHORT NOTICE QUESTION

PURCHASE OF SARUS TOWERS

12. **SHRI JYOTIRMOY BOSU:** Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Shipping (Lighthouse Department) is going to purchase 13 more Sarus Towers immediately from abroad;

(b) is it a fact that this Sarus Tower already purchased has been found to be defective; and

(c) if so, will the Government give details and stop making further purchases of these equipments?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Government has sanctioned the purchase of 16 Sarus Towers for marking the deep water channel in the Gulf of Kutch leading to the off-shore oil terminal at Salaya to be used by VLCCs (Very